

(1)	(2)	(3)
3.	<i>Cochin Shipyard Limited, Cochin:</i>	
	(i) Dry Dock	270.00 x 44.8 x 11.5
	Two Quays	290 x 7.5 208
4.	<i>Calcutta Port Trust, Calcutta:</i>	
	(i) No. 1 Kidderpore Dock	157.01 x 19.51 x 8.0
	(ii) No. 2 Kidderpore Dock	143.29 x 19.51 x 8.3
	(iii) No. 3 Kidderpore Dock	102.13 x 14.63 x 7.8
	(iv) No. 1 Netaji Subhash Dock	172.26 x 22.87 x 10.0
	(v) No. 2 Netaji Subhash Dock	176.85 x 22.87 x 10.0
5.	<i>Hooghly Dock & Port Engineers Ltd., Calcutta:</i>	
	(i) Salkia Dry Dock	92.0 x 11.0 x 7.0
6.	<i>Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam:</i>	
	(i) Dry Dock	240.0 x 38.0 x 8.10 Can take upto 57,000 DWT but size limited to 640 ft.
	Basin	Two arms 225 - 167 accommodate 40,000 DWT.
7.	<i>Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. Calcutta.</i>	
	West Basin and River Side Jetty	
	(B) Private Sector	
1.	<i>Western India Shipyard Ltd. Goa</i>	
	(i) Floating Dry Dock	210 x 42 Capacity 20,000 T lifting capacity
	(ii) One Graving Dock	For docking ship 85 x 14 M size.
	(iii) One Repair Jetty	160
2.	<i>Chakhani International Ltd., Madras</i>	
	Two Floating Docks	(i) 14,000 T lifting capacity 190 x 32 (ii) 2400 T lifting capacity 100 x 19
3.	<i>Magdala Shipyard Ltd., Sural</i>	
	Shiplift	125.0 x 22.5 x 5.5

Allocation for improvement of National Highways in Andhra Pradesh

3131. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the allocation for improvement of National Highways in Andhra Pradesh in 1996-97, district-wise; and

(b) the steps proposed to improve the National Highways in West and East-Godavari districts in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) The following allocation of funds has been made for improvement of National Highway in Andhra Pradesh during 1996-97:

(i) Original works' Rs. 21.00 crores

(ii) Externally Aided Projects Rs. 16,00 crores

The allocation is made for the entire State and not district-wise

(b) The National Highway No. 5 passes through West and East Godavari districts. Improvement works like Eluru bypass, strengthening of Km 44 to 75 and other works all totalling to Rs. 143.55 crores have been sanctioned. Further, under Annual Plan 1996-97, there is a provision for strengthening of 15 Km of N.H. 5 at an estimated cost of Rs. 3.00 crores.

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3132. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) गुजरात के प्रत्येक जिले में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम के अनुसार गुजरात संचार सुविधाओं के मामले में पिछड़ रहा है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज प्रार्थियों को टेलीफोन-कनेक्शन जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा): (क) से (ग) वार्षिक रिपोर्ट 1995-96 में उपलब्धियों से संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं। इसमें विकास संबंधी कोई भी लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 2.12 लाख प्रतीक्षा सूची के प्रति गुजरात में वर्ष 1996-97 के लिए 1.88 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Plan for construction of bypasses during Ninth Five Year Plan

3133- DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the National Highways Authority of India plans to construct 40 city bypasses in the country during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, whether they have already identified 27 city bypasses;

(c) by when the remaining 13 bypasses are likely to be selected;

(d) whether Government have made provisions of about Rs. 120 crore for acquisition of land for bypasses; and

(e) the total amount involved and by what time the work is likely to be started?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRIT.G. VENKATRAMAN): (a) to (e) The National Highways Authority of India have identified 35 bypasses and propose to develop them on B.O.T. basis. The projects are at conceptual stage only and hence it is too early to indicate any details.

भोपाल पारपत्र कार्यालय में संबंधित आवेदन-पत्र

3134. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में 30 जून, 1996 तक कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ख) विलंब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में 30.6.96 को विलंबित आवेदनों की संख्या 2743 है।

(ख) पासपोर्ट सामान्यतया स्पष्ट पुलिस साक्षात्कन रिपोर्ट पर अथवा साक्षात्कन हेतु पुलिस को पत्र भेजे जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर, दोनों में से जो भी हो, और "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर जारी किए जाते हैं। यद्यपि आवेदनों पर कार्रवाई करने में देर नहीं की जाती है, तथापि, ऐसे मामले होते रहते हैं जिनमें निम्नलिखित कारणों से पासपोर्ट जारी करने विलंब हुआ है: संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक अथवा अधूरी रिपोर्ट प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों, विशेषरूप से छक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के दस्तावेजों में विसंगति, आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने पर उनके प्रत्युत्तर न मिलना। ऐसे सभी मामलों में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि पुलिस साक्षात्कन रिपोर्ट त्वरित गति से भेजी जाए तथा संबंधित आवेदकों से कहता है कि वे अपेक्षाओं को पूर्ण करें और अपने आवेदन पत्रों में रह गई कमियों को पूरा करें ताकि